

भारत में विकासात्मक समूह

भारत में विकासात्मक समूह

स्वयं सहायता समूह (SHG)

- ⌚ समान सामाजिक-आर्थिक प्रष्ठभूमि और रुचियों वाले लोगों का स्व-शासित सहकर्मी-नियंत्रित (Peer-Controlled) सूचना समूह
- ⌚ सदस्यों की अनुमति: 5-20 | पंजीकरण आवश्यक नहीं
- ⌚ SHG सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिये बचत राशि का उपयोग करते हैं
- ⌚ नाबार्ड का SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (1992)- SHG को औपचारिक बैंकिंग संस्थाओं से जोड़ना
- ⌚ भारत में ~ 88% SHG में सभी महिला सदस्य हैं
- ⌚ सफलता की कहानियाँ:
 - ⌚ वर्ष 1972 से स्व-रोजगार महिला संघ (SEWA)
 - ⌚ केरल में कुडुम्बश्री (वर्ष 1998)

सहकारी समितियाँ

- ⌚ जन-केंद्रित उद्यम, जो अपने सदस्यों के स्वामित्व में उनके द्वारा नियंत्रित और उनके लिये संचालित होते हैं।
- ⌚ सदस्यों के साझा योगदान के माध्यम से एकत्रित की गई पूँजी।
- ⌚ विनियमन अधिनियम:
 - ⌚ बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002
 - ⌚ राज्य सहकारी समिति अधिनियम
- ⌚ 97वाँ संविधान संशोधन (2011):
 - ⌚ सहकारी समितियाँ निर्माण करने का अधिकार - एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c))
 - ⌚ अनुच्छेद 43B (DPSP) - सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
 - ⌚ भाग IX-B जिसका शीर्षक है "सहकारी समितियाँ" (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT)।
- ⌚ उदाहरण: अमूल, इफको और पैक्स

गैर-सरकारी संगठन (NGO)

- ⌚ पीड़ा को दूर करने, निर्धनों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण का संरक्षण करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने या सामुदायिक विकास के लिये गतिविधियाँ संचालित करना।
- ⌚ पंजीकृत:
 - ⌚ सोसायटी: सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860
 - ⌚ ट्रस्ट: भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882
 - ⌚ कंपनियाँ: धारा 8 कंपनी अधिनियम, 2013
- ⌚ संवैधानिक प्रावधान:
 - ⌚ अनुच्छेद 19(1)(c)- संघ बनाने का अधिकार
 - ⌚ अनुच्छेद 43- ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
 - ⌚ समवर्ती सूची में धर्मार्थ संस्थाओं का उल्लेख है

FCRA विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक सभी गैर सरकारी संगठनों के लिये पंजीकरण अनिवार्य करता है।

प्रमुख NGO:

- ⌚ NGO प्रथम: ग्रामीण भारत में बच्चों के सीखने के स्तर का आकलन करने के लिये ASER रिपोर्ट की अगुआई की।
- ⌚ अक्षय पात्र फाउंडेशन: स्कूली बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न मोजन उपलब्ध कराया।

NGO- दर्पण प्लेटफॉर्म - NGO और सरकारी निकायों के बीच एक इंटरफेस।



और पढ़ें: [SHG](#) के माध्यम से महिला-सशक्तीकरण पर SBI का अध्ययन, [NGO](#) का FCRA पंजीकरण रद्द करना, [भारत का सहकारी क्षेत्र](#)।

